

4

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 42/2022

GCMS CASE NO-2022/42

1. हर्षपिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख साकिन 32 एच करणपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांत

बनाम :

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़।

रेसपोडेंट

—:निर्णय:—

दिनांक : 20.03.2024



अपील में सामान्य तथ्य यह है कि ये बानारागी आदेश उपतहसीलदार (राजस्व), राजियासर अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांत को चक 4 डीडब्ल्यूएम के प.न. 157/01 में 6.325 है० भूमि पर फसल रबी 2078 में नाजायज काश्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने का नोटिस जारी किया गया।

उपतहसीलदार राजियासर ने अपीलांत को अतिक्रमी माना जाकर मालगुजारी का 50 प्रतिशत तावान, खडी फसल नीलाम करने व प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर भूमि बहक सरकार प्राप्त करने की आज्ञापारित की है।

वकील अपीलांत श्री सुरेन्द्र सुथार की बहस सुनी गई व अपील के तथ्यों का मनन किया गया। अपील के अनुसार अदालत मातहत ने नैसर्गिक न्याय व निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं की है। फसलकुन्ता (Assesment) नीलामी, 50 गुणातावान व बेदखली तीनों आदेश एक साथ देकर गैर कानूनी आदेश पारित किया है। अपीलांत को पहले कभी बेदखल नहीं किया गया। ऐसे में उन्हें पाश्चावर्ती अतिक्रमी मानकर भी भूल की है। तीनों दण्ड एक साथ कानूनन नहीं दिये जा सकते।

पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांत हर्षपिंदर सिंह द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गई है। अपीलांत द्वारा अपने पक्ष में किराी प्रकार साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया जिससे जैर प्रकरण भूमि पर उसका हक/हकूक साबित अपीलांत द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण ही जैर अपील निर्णय पारित किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)
880

(5)

गया है। की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अपीलांट अतिक्रमी साबित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 28.01.2022 यथावत रखा जावे।

मातहत अदालत का रिकार्ड शामिल पत्रावली हो चुका है। रिकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर अपीलांट को नोटिस अन्तर्गत धारा 22 विधिवत रूप से जारी किया गया व अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ है। नोटिस में अपीलांटस को अवसर दिया गया कि वें आगामी निर्धारित तारीख पेशी 28.01.2022 से पूर्व अतिक्रमित भूमि खाली कर देवें। बाद नोटिस तामील होने के उपरांत भी अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया है। तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय सिद्धांतो व स्थापित विधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन में न होने से आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। स्थगन प्रार्थन पत्र व अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति पत्रावली में शामिल की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कन्हैया लाल सोनगर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ (आ. गणानगर)
सूरतगढ